पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने विकास प्राधिकरणों के आडिट कराने के निर्णय को स्वागत योग्य बताया
मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

लखनऊः 12 अप्रैल, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विकास प्राधिकरणों का कैग से आडिट कराये जाने के निर्णय का स्वागत किया है। राज्यपाल ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पारदर्शिता और शुचिता की दृष्टि से जहाँ भी सरकारी धन का उपयोग होता है, उसका आडिट होना चाहिये। उन्होंने कहा कि इससे जहाँ एक ओर धन के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा वहीं स्वयं को भी समाधान होता है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश ने 5 मई, 2016 एवं 1 जून, 2016 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया था कि राज्य सरकार द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्राप्तियों का आडिट किये जाने हेतु स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को 5 मई, 2016 एवं 31 मई, 2016 को पत्र भेजकर यथोचित कार्यवाही कर अवगत कराने को कहा गया था। राज्यपाल द्वारा 25 जुलाई, 2016 को तीसरी बार मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर 'भारत का संविधान' एवं अन्य कानून के प्राविधानों पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्राप्तियों का आडिट कराने के आदेश देने के लिए कहा गया था। परन्तु राज्य सरकार की ओर से संबंधित विभाग एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आडिट कराने के संबंध में आदेश निर्गत नहीं किये गये जिस कारण महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर आडिट) द्वारा प्राधिकरण का आडिट किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। राज्यपाल ने प्रकरण की महत्ता को देखते हुये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय वित्तमंत्री को इस संबंध में पत्र प्रेषित किये थे।

अंजुम/ललित/राजभवन (132/11)